



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 77] प्रयागराज, शनिवार, 06 मई, 2023 ई० (बैशाख 16, 1945 शक संवत्) [संख्या 18

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	247—251	3075	भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	523—544	1500	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975	भाग 6—क—भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख—नगर पंचायत, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	173—198	975	भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		975
			भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
			भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
			भाग 8—सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	243—245	975
			स्टोर्स-पर्वेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

बेसिक शिक्षा विभाग

अनुभाग-1

10 नवम्बर, 2022 ई0

सं0 228/2022/3144/अरसठ-1-2022-33(59)/2019-महानिदेशक, स्कूल शिक्षा (डी0जी0एस0ई0) का पद शासन के कार्यालय आदेश संख्या-4209/अरसठ-1-2019-33(59)/2019, दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 द्वारा सृजित करते हुए उक्त पद पर भारतीय प्रशासकीय सेवा के सचिव स्तर के अधिकारी/राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान के समकक्ष स्तर के अधिकारी को तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। तत्क्रम में शासन के कार्यालय आदेश संख्या-4909/5/2019/अरसठ-1-2019-33(59)/2019, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 द्वारा महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के कार्य एवं दायित्व निर्धारित किये गये हैं।

2-राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर कक्षा-12 तक की एकीकृत शिक्षा व्यवस्था की संकल्पना की गयी है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने हेतु एवं एकीकृत स्कूल शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंशा के अनुरूप मूर्त रूप देने के लिये, बेसिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु तथा शासन के समक्ष स्कूल शिक्षा का समन्वित रूप प्रस्तुत करने की मंशा से महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के कार्य एवं दायित्वों में माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित कार्य एवं दायित्वों को सम्मिलित करते हुए विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3-अतएव श्री राज्यपाल एतद्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन समस्त निदेशालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यकारी/प्रशासनिक नियंत्रण एवं बेसिक शिक्षा विभाग में संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं के त्वरित गति से संचालन एवं प्राथमिक शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार एवं शिक्षकों की दक्षता वृद्धि हेतु सृजित महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 के पद हेतु कार्यालय आदेश संख्या 4909/5/2019/अरसठ-1-2019-33(59)/2019, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 द्वारा निर्धारित कार्य एवं दायित्व को विस्तारित कर माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त निदेशालय को समाहित करते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग का विभागाध्यक्ष नामित करते हुए एतद्वारा समस्त वित्तीय एवं प्रशासकीय अधिकार प्रदान किये जाते हैं।

4-महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के कार्य एवं दायित्व विषयक शासन के कार्यालय आदेश दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 द्वारा निर्धारित कार्य एवं दायित्वों को विस्तारित करते हुए श्री राज्यपाल महोदया महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त निदेशालय/कार्यालयों को समेकित करते हुए निम्नलिखित कार्य/दायित्व सौंपे जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं-

- (1) समस्त निदेशालयों के निदेशकों के मध्य समन्वयन का प्रभावी पर्यवेक्षण।
- (2) समस्त निदेशालयों के समस्त प्रस्तावों/सूचनाओं एवं आख्याओं का परीक्षण कर शासन को प्रेषित करना।
- (3) बजट प्रस्ताव प्राप्त कर परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना।
- (4) निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृतियाँ, बजट आवंटन, व्यय एवं निधियों के प्रवाह का प्रभावी पर्यवेक्षण।
- (5) निदेशालय से उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराना।
- (6) पी0एफ0एम0एस0 आधारित प्रणाली के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण।
- (7) समस्त भर्ती प्रक्रियाओं, स्थानान्तरण, सेवा संबंधी मामलों का निस्तारण निदेशक के माध्यम से सम्पादित कराना।
- (8) निदेशक के माध्यम से अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार कराना एवं ट्रेनिंग माड्यूल तैयार कराकर प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना।
- (9) समस्त मानव संसाधन का प्रबन्धन निदेशक के माध्यम से करवाना तथा उसका पर्यवेक्षण करना।

(10) उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा सम्पादित किये जा रहे समस्त कार्यों को निदेशक के माध्यम से सम्पादित कराना, उसका पर्यवेक्षण करना एवं प्रशासनिक नियंत्रण करना।

(11) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संकल्पना के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं में सुधार करवाना एवं प्रभावी पर्यवेक्षण करना।

(12) संस्कृत शिक्षा परिषद् से संबंधित कार्यों को निदेशक के माध्यम से सम्पादित कराना और उसका प्रभावी पर्यवेक्षण करना।

(13) माध्यमिक निदेशालय के अधीन मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण करना।

(14) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत मानव सम्पदा प्रणाली विकसित कराकर लागू करवाना।

(15) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के आंकड़ों हेतु एकीकृत पोर्टल विकसित कराकर क्रियाशील बनवाना।

(16) निदेशक, माध्यमिक की वार्षिक गोपनीय आख्या हेतु प्रस्तावक अधिकारी होंगे।

5—महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को शिक्षा निदेशक (मा0) की वार्षिक गोपनीय आख्याओं हेतु प्रस्तावक अधिकारी बनाये जाने के दृष्टिगत इस सम्बन्ध में पूर्व में समय-समय पर निर्गत समस्त शासनादेश/नियम/विनियम अवक्रमित समझे जायेंगे।

27 जनवरी, 2023 ई0

नियुक्ति

सं0 04/2023/नव0नि0-259/अरसठ-1-2022-33(39)/2021—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा-2020 के आधार पर वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 के प्रयागराज के पत्र संख्या 40/02/ई-3/2020-21, दिनांक 14 जुलाई, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये निम्नलिखित अभ्यर्थी को बेसिक शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 में वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पद पर छठे वेतनमान, वेतन बैंड-3 रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवे वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित पे-बैंड 3,56,100-1,77,500, ग्रेड पे लेवल-10) में औपबधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

क्र0	लो0से0आ0 का क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम (सर्व श्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पता
1	2	3	4	5	6
1	37	125163	हरिओम सिंह	राम बचन सिंह	स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता— मलाक मय भैसाही, पोस्ट—गारापुर, प्रयागराज, उ0प्र0, पिन—221507

2—उपर्युक्त अभ्यर्थी निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। उक्त नवनियुक्त अधिकारी के जनपद/विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3—उपर्युक्त अभ्यर्थी की वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पद पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों एवं उपबंधों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा अवधि पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे। अलग-अलग मामलों में परीक्षा अवधि को बढ़ा सकते हैं।

(2) सम्बन्धित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य अनुमन्य भत्ते भी देय होंगे।

(3) सम्बन्धित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 01 माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तदनुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(4) उक्त अंकित तालिका में उल्लिखित वे अभ्यर्थी जो दूसरे विभागों में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवाएं छोड़कर बेसिक शिक्षा विभाग में योगदान देते हैं तो उन्हें अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(5) सम्बन्धित अभ्यर्थी इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आदि के सम्बन्ध में यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है, तो उनकी सेवाएं बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।

(6) यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता या उम्मीदवार द्वारा उसके स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(7) सम्बन्धित अभ्यर्थी की विभागीय अधिकारियों के साथ पारस्परिक जयेष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(8) बेसिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पद पर कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं को उपलब्ध करायें—

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के सम्बन्ध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

(ग) निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा।

(घ) एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

(ङ) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

20 फरवरी, 2023 ई0

सं0 13/2023/नव0नि0-01/अरसठ-1-2023-33(39)/2021—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा-2020 के आधार पर वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के प्रयागराज के पत्र संख्या-40/02/ई-3/2020-21, दिनांक 14 जुलाई, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये निम्नलिखित अभ्यर्थी को बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 में वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पद पर छठे वेतनमान, वेतन बैंड-3 रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवे वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित पे-बैंड-3,56,100-1,77,500, ग्रेड पे लेवल-10) में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

क्र0 सं0	लो0से0आ0 का क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम (सर्व श्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पता
1	2	3	4	5	6
1	34	584225	मातृ प्रसाद मिश्र	चन्द भूषण	स्थायी पता/पत्र-व्यवहार का पता— ग्राम व पोस्ट—चिल्ला गौहानी, थाना—लालापुर, जिला—प्रयागराज, उ0 प्र0, पिन—212107

2—उपर्युक्त अभ्यर्थी निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। उक्त नवनियुक्त अधिकारी के जनपद/विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3—उपर्युक्त अभ्यर्थी की वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पद पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों एवं उपबंधों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा अवधि पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे। अलग-अलग मामलों में परीक्षा अवधि को बढ़ा सकते हैं।

(2) सम्बन्धित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य अनुमन्य भत्ते भी देय होंगे।

(3) सम्बन्धित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 01 माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तदनुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(4) उक्त अंकित तालिका में उल्लिखित वे अभ्यर्थी जो दूसरे विभागों में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवाएं छोड़कर बेसिक शिक्षा विभाग में योगदान देते हैं तो उन्हें अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(5) सम्बन्धित अभ्यर्थी इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आदि के सम्बन्ध में यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है, तो उनकी सेवाएं बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।

(6) यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता या उम्मीदवार द्वारा उसके स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(7) सम्बन्धित अभ्यर्थी की विभागीय अधिकारियों के साथ पारस्परिक जयेष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(8) बेसिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पद पर कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं को उपलब्ध करायें—

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के सम्बन्ध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

(ग) निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा।

(घ) एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

(ङ) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 06 मई, 2023 ई० (बैशाख 16, 1945 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय,
विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD [ESTABLISHMENT SECTION]

NOTIFICATION

February 02, 2022

No. 113—From the date of taking over charge, following Joint Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Registrar, in the pay scale Level-13A :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	3253	Sri Deena Nath

No. 114—From the date of taking over charge, following Deputy Registrars, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Joint Registrar, in the pay scale Level-13 :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
(Sri/Smt./Km.)—		
1	3354	Kamlesh Kumar Yadav
2	3357	Arti
3	3362	Nekahat Ayasha

(Under Rule 20(d) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, the promoted Joint Registrars shall undergo four and half months training, particularly with regard to application of Law in the working of the High Court, conducted by J.T.R.I., Lucknow and 90% attendance shall be compulsory during training programme. The Director, J.T.R.I. shall certify whether such Joint Registrars have successfully completed the training. The term “successful training” shall mean 90% attendance in training programme conducted by J.T.R.I.)

No. 115—From the date of taking over charge, following Assistant Registrars, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Deputy Registrar, in the pay scale Level-12 :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S./Sri.)—
1	4043	Brij Nath
2	4049	Kuldeep Kumar Srivastava
3	4067	Nikhilesh Chandra Pathak

No. 116—From the date of taking over charge, following Section Officers, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, are hereby promoted as Assistant Registrars, in the pay scale Level-11:

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S./Sri.)—
1	7082	Yogendra Kumar Singh
2	2948	Haleem Uddin Mohd. Tariq, <i>Lko.</i>
3	7056	Sushil Kumar

No. 117—From the date of taking over charge, following Review Officers, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, are hereby promoted as Section Officer, in the pay scale Level-10 :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(Sri./Ms.)—
1	7469	Adarsh Kumar Gautam, <i>Lko.</i>
2	7470	Meenu, <i>Lko.</i>
3	7477	Sushma Khare

(All promotions, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Vipin Kumar Yadav (Emp. No. 2707), Registrar and Ms. Pannu Yadav (Emp. No. 7350), Section Officer, both posted at Lucknow Bench of this Court and drawing salary from High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court; Sri Farooq Ahmad Siddiqui (Emp. No. 3453), Joint Registrar, Sri Mahish Kumar Dubey (Emp.

No. 3460), Joint Registrar, Sri Pradeep Kumar Kaushal (Emp. No. 4059), Deputy Registrar, Sri Vivekanand Sharma (Emp. No. 4048), Deputy Registrar and Sri Jayanta Chatterjee (Emp. No. 4060), Deputy Registrar, all posted at High Court of Judicature at Allahabad and drawing salary from Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad. Further, Sri Kamlesh Kumar Yadav (Emp. No. 3354), Smt. Arti (Emp. No. 3357) and Km. Nekah at Ayasha (Emp. No. 3362), all posted at High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as joint Registrar, Sri Brij Nath (Emp. No. 4043), Sri Kuldeep Kumar Srivastava (Emp. No. 4049) and Sri Nikhilesh Chandra Pathak (Emp. No. 4067), all posted at High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Deputy Registrar; Sri Haleem Uddin Mohd. Tariq (Emp. No. 2948), posted at Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad upon promotion as Assistant Registrar, Sri Adarsh Kumar Gautam (Emp. No. 7469) and Ms. Meenu (Emp. No. 7470), both posted at Lucknow Bench of this Court, will draw Salary from High Court of Judicature at Allahabad upon promotion as Section Officer).

No. 118—From the date of taking over charge, Sri Vijay Shanker Dubey-II, Joint Registrar-cum-Bench Secretary Grade-IV, (Emp. No. 3119), High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Registrar-cum-Principal Bench Secretary, High Court of Judicature at Allahabad, in the pay scale of Rs.1,31,100-2,16,600, level-13-A in the vacancy caused due to retirement of Sri Brijesh Kumar.

No. 119—From the date of taking over charge, Sri Satya Nand Pandey, Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, (Emp. No. 3380), High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Joint Registrar-cum-Bench Secretary Grade-IV, High Court of Judicature at Allahabad, in the pay scale of Rs. 1,23,100-2,15,900, level-13 in the vacancy caused due to promotion of Sri Vijay Shanker Dubey-II.

No. 120—From the date of taking over charge, Sri Anil Kumar Singh, Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, (Emp. No. 4806), High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow in the pay scale of Rs. 78,800-2,09,200, level-12 in the vacancy caused due to retirement of Sri Radhey Shyam Verma, *Lko*.

No. 121—From the date of taking over charge, Sri Vinay Kumar Sharma, Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, (Emp. No. 4070), High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow in the pay scale of Rs.78,800-2,09,200, level-12 in the vacancy caused due to retirement of Sri Om Prakash.

No. 122—From the date of taking over charge, Sri Mohd. Khalid Iqbal, Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, (Emp. No. 6064), High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad, in the pay scale of Rs.78,800-2,09,200, level-12 in the vacancy caused due to promotion of Sri Satya Nand Pandey.

(The promotion, notified above, shall be subject to result of Writ Petition (s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, S/Sri Anil Kumar Singh (Emp.No. 4806) and Vinay Kumar Sharma, (Emp. No. 4070), High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow shall draw salary from High Court, Allahabad as D.R.-cum-B.S. Grade-III. S/Sri Mahendra Nath (Emp. No. 6094), D.R.-cum-B.S. Grade-III, Sant Raj Kumar (Emp. No. 2956), A. R.-cum-B.S. Grade-II and Mrs. Nanda Priya (Emp. No. 2978) A.R.-cum-B.S. Grade-II, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow who have been permitted to draw salary from High Court, Allahabad shall draw salary from High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow).

February 19, 2022

No. 125-Sri Sandeep Kumar Pandey (Emp. No. 7466), Review Officer, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is notionally promoted as Section Officer in the pay scale Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500) *w.e.f.* 01-01-2022 (*i.e.* the date his junior Mrs. Pratibha Gupta (Emp. No. 7467) has been promoted as Section Officer) along with all consequential benefits. His name is placed above the name of Mrs. Pratibha Gupta (Emp. No. 7467) in the gradation list of Section Officer.

(in view of prevailing transfer policy, he will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad as Section Officer).

(The promotion shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

March 02, 2022

No. 126-From the date of taking over charge, following Joint Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Registrar, in pay scale Level-13A (Rs. 1,31,100-2,16,600) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	3255	Sri Shiv Shampat Singh

No. 127-From the date of taking over charge, following Deputy Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Joint Registrar, in pay scale Level-13 (Rs. 1,23,100-2,15,900) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	3368	Sri Ram Bahadur

(Under Rule 20(d) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, the promoted Joint Registrars shall undergo four and half months training, particularly with regard to application of Law in the working of the High Court, conducted by J.T.R.I. Lucknow and 90% attendance shall be compulsory during training programme. The Director, J.T.R.I. shall certify whether such Joint Registrars have successfully completed the training. The term "successful training" shall mean 90% attendance in training programme conducted by J.T.R.I.)

No. 128-From the date of taking over charge, following Assistant Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Deputy Registrar, in pay scale Level-12 (Rs. 78, 800-2, 09, 200):

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	4063	Sri Satish Kumar Pushkar

No. 129-From the date of taking over charge, following Section Officers, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Assistant Registrar, in pay scale Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S./Sri.)—
1	7067	Abhishek Srivastava -I
2	7043	Pradeep Kumar Malviya

No. 130-From the date of taking over charge, following Review Officers, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Section Officer, in pay scale Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(Ms./Sri.)—
1	7478	Priyadarshini Verma
2	7479	Dhirendra Kumar Kushwaha

(All promotions, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Jilay Dar Singh (Emp. No. 3346), Joint Registrar and Sri Brij Nath No. 4043), Deputy Registrar, both posted at High Court of Judicature at Allahabad and drawing salary from Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad. Further, Sri Ram Bahadur (Emp. No. 3368), posted at High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Joint Registrar; Sri Satish Kumar Pushkar (Emp. No. 4063), posted at High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Deputy Registrar).

March 29, 2022

No. 131-From the date of taking over charge, following Review Officer, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Section Officer, in pay scale Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	7481	Sri Balramji Varma

(The promotion shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

By order of the Hon'ble Court,
ASHISH GARG,
Registrar General.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

[ESTABLISHMENT SECTION]

CORRIGENDUM

October 15, 2022

No. 6369/Establishment—In partial modification, the words "Km. Nekahat Ayasha (Emp. No. 3362), Joint Registrar" included in following order of Notification No. 46 to 48 dated October 01, 2022, stand omitted :

"In view of prevailing transfer policy, Smt. Arti (Emp. No. 3357), Joint Registrar, Km. Nekahat Ayasha (Emp. No. 3362), Joint Registrar, Sri Sanjay Kumar (Emp. No. 4079), Deputy Registrar and

Sri Soumitra Mazumdar (Emp. No. 4081), Deputy Registrar, all posted at High Court of Judicature at Allahabad and drawing salary from Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad....."

Km. Nekahat Ayasha (Emp. No. 3362), Joint Registrar, will continue to draw her salary from Lucknow Bench of this Court.

(Sd.) ILLEGIBLE,
ASHISH GARG,
Registrar General.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

[ADMINISTRATIVE (A-3) SECTION]

NOTIFICATION

January 07, 2023

No. 03/Main-B/Admin (A-3)--In exercise of the powers conferred under section 5(2) of the U. P. Dacoity Affected Areas Act, 1983, the High Court is pleased to appoint Sri Rajeev Kumar Paliwal, Additional District & Sessions Judge, Mahoba, as Special Judge to preside over the Special Court constituted under Section 5(1) of the said Act *vide* State Government's Notification no. 2470/VII-Nyaya-2-2005-221/81, dated September 29, 2005 for disposal of the cases relating to Dacoity Affected Areas Act, 1983, in the District Mahoba.

By order of the Court,
ASHISH GARG,
Registrar General.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

[ESTABLISHMENT SECTION]

OFFICE ORDER

March 13, 2023

No. 11034/Establishment--Under the orders of the Learned Registrar General dated March 03, 2023 with reference to your application dated January 05, 2023 regarding updation your surname and marital status in the service records, you are hereby informed that the in view of affidavit dated February 08, 2023 and the marriage registration certificate issued by the Marriage Registration Officer, Lucknow, your surname and marital status has been updated from 'Ms. Divya Bharti' to 'Smt. Divya Singh' in the service records.

Smt. Divya Singh (Emp. No. 3838)

Additional Private Secretary,

High Court of Judicature at Allahabad,

Lucknow Bench, Lucknow.

(Sd.) ILLEGIBLE,
Registrar,
Establishment.

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, वाराणसी
प्रारूप-19

[नियम-27 का उपनियम (1)]
(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

अधिसूचना

25 अप्रैल, 2023 ई0

सं0 1510 / आठ-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0) / वाराणसी-भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा जनपद चन्दौली में फ्रेट विलेज परियोजना में भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, वाराणसी हेतु जिला-चन्दौली, तहसील-पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर, परगना-राल्हुपुर, में स्थित कुल योग भूमि 25.58628 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना सं0 610 दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा स्थानीय समाचार-पत्र में दिनांक 05 नवम्बर, 2022 को प्रकाशित किया गया था। उपजिलाधिकारी पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर, चन्दौली को परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया है। जिनके द्वारा परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारों के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत की गयी है।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोंपरान्त धारा 19 (1) के अन्तर्गत मा0 राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रायोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला-चन्दौली, तहसील-पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर, परगना-राल्हुपुर, ग्राम-ताहिरपुर व मिल्कीपुर की उक्त अनुसूची में वर्णित 25.58628 हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र रूप में चिन्हित किया है।

मा0 राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सांराश के प्रकाशन हेतु समुचित सरकार जिला कलेक्टर, चन्दौली को निर्देशित करते हैं :

अनुसूची-क

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
चन्दौली	पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर	राल्हुपुर	ताहिरपुर	1/1	हेक्टेयर 0.0510
				2/1	0.5940
				2/2	0.2460
				2/69-मि	0.0124
				2/69-मि	0.0114
				2/69-मि	0.0164
				2/69-मि	0.0124
				2/69-मि	0.0114
				2/69-मि	0.0115
				3	0.0400
				4	0.1740

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
चन्दौली	पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर	राल्हूपुर	ताहिरपुर	5/1-मि	0.0590
				5/1-मि	0.0201
				5/1-मि	0.0570
				5/1-मि	0.0570
				5/1-मि	0.0590
				5/1-मि	0.0590
				5/1-मि	0.0590
				5/2-मि	0.3277
				5/3	0.0810
				5/4-मि	0.0650
				5/4-मि	0.7820
				5/4-मि	0.7430
				5/4-मि	0.1300
				5/4-मि	0.1537
				5/4-मि	0.6480
				5/9-मि	0.2630
				5/10-मि	0.1067
				5/10-मि	0.1067
				5/11-मि	0.0714
				5/11-मि	0.0714
				5/12-मि	0.3640
				5/5-मि	0.0966
				5/6-मि	0.0696
				5/6-मि	0.0696
				5/7-मि	0.1164
				5/7-मि	0.1164
				5/8-मि	0.5260
				6-मि	0.0410
				6-मि	0.0380
				6-मि	0.0390
				6-मि	0.0380
				6-मि	0.0380
				6-मि	0.0390
				6-मि	0.0380
				10-मि	0.0099
				10-मि	0.1187

1	2	3	4	5	6
चन्दौली	पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर	राहूँपुर	ताहिरपुर	10-मि	हेक्टेयर 0.1187
				10-मि	0.5474
				10-मि	0.1516
				24-मि	0.0330
				24 / 1-मि	0.0950
				24 / 1-मि	0.1250
				24 / 1-मि	0.0500
				24 / 1-मि	0.6683
				24 / 1-मि	0.0160
				24 / 1-मि	0.0294
				24 / 1-मि	0.2216
				24 / 1-मि	0.3985
				24 / 1-मि	0.1530
				24 / 1-मि	0.0840
				24 / 3	0.0260
				24 / 3-मि	0.0342
				25-मि	0.0650
				25-मि	0.0200
				25-मि	0.0200
				25-मि	0.0350
				25-मि	0.2340
				27-मि	0.1050
				27-मि	0.0140
				28-मि	0.2010
				28-मि	0.0300
				29 / 1-मि	0.0080
				29 / 1-मि	0.0290
				29 / 2-मि	0.0360
				30	0.0080
				32 / 2	0.0650
				32 / 3	0.2630
				33	0.0610
				33-मि	0.1740
				34	0.0890
				35	0.2390
				36-मि	0.0740
				36-मि	0.1130
				36-मि	0.1130

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
चन्दौली	पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर	राहूँपुर	ताहिरपुर	36-मि	0.0400
				37-मि	0.1500
				38	0.2390
				40	0.1380
				41-मि	0.1200
				41-मि	0.3200
				41-मि	0.0890
				41-मि	0.2280
				42 / 1-मि	0.0360
				46-मि	0.1450
				46-मि	0.4550
				47-मि	0.0530
				47 मि	0.4750
				47-मि	0.0930
				47-मि	0.0560
				47-मि	0.0700
				47-मि	0.0530
				48-मि	0.0310
				48-मि	0.0930
				48-मि	0.1540
				49-मि	0.0600
				49-मि	0.1420
				49-मि	0.0250
				49-मि	0.1660
				49-मि	0.0400
				54	0.1540
				55-मि	0.1130
				55-मि	0.0960
				55-मि	0.1710
				55-मि	0.0120
				55-मि	0.0830
				55-मि	0.0890
				56-मि	0.0210
				56-मि	0.0080
				56-मि	0.0600
				56 / 2-मि	0.0040
				57 / 1-मि	0.0280
				57 / 2-मि	0.0050
				योग . .	15.9211

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
चन्दौली	पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर	राल्हूपुर	मिल्कीपुर	8/1	0.01500
				8/3	0.01343
				9/1 मि	0.06400
				9/1 मि	0.02000
				10/2	0.15980
				10/3	0.13400
				11	0.09300
				12	0.29500
				13 मि	0.10800
				13 मि	0.10800
				13 मि	0.21600
				14	0.08100
				15	0.01200
				16	0.40100
				17	0.16200
				17/77	0.19000
				18	0.04000
				19 मि	0.39784
				20	0.21977
				21/2	0.08680
				22	0.02256
				23 मि	0.01200
				23/1 मि	0.02800
				23/3	0.09880
				24/1 मि	0.18163
				24/2	0.04900
				25	0.23178
				27/3	0.47270
				27/2	0.01500
				27/4 मि	0.07700
				27/5	0.06070
				27/6	0.27500
				28	0.51400
				29	0.36800
				30/1 मि	0.06710
				30/2	0.02690
				32 मि	0.05200
				32 मि	0.05290

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
चन्दौली	पं० दीनदयाल	राल्हूपुर	मिल्कीपुर	32 मि	0.22400
	उपाध्याय नगर			33 मि	0.09700
				34 मि	0.02131
				34 मि	0.01350
				34 मि	0.01350
				35	0.18280
				36	0.06500
				37 मि	0.00100
				38	0.09300
				39	0.03036
				40	0.13400
				41	0.01200
				42	0.02400
				43	0.00400
				44	0.06900
				45	0.09700
				46	0.15800
				47	0.19000
				48 मि	0.27500
				48 मि	0.04000
				48 मि	0.06100
				49	0.14070
				54	0.12900
				56	0.06500
				57 / 1	0.15400
				57 / 2 मि	0.06650
				57 / 2	0.10900
				61	0.26920
				62 / 1	0.10100
				62 / 2	0.10900
				63 / 2	0.26300
				62 / 3	0.00540
				64	0.09300
				65	0.13820
				66	0.04000
				67	0.17320
				68	0.14600
				70	0.42780
				75	0.00800
				योग . .	9.66518

अनुसूची-ख

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
चन्दौली	पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर	राल्हूपुर	ताहिरपुर	27/2	हेक्टेयर 0.1500

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, चन्दौली के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना
(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा जनपद चन्दौली में फ्रेट विलेज परियोजना में भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, वाराणसी हेतु जिला चन्दौली, तहसील—पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर, परगना—राल्हूपुर, में स्थित कुल योग भूमि 25.58628 हे0 भूमि के लिए प्रकाशित अधिसूचना संख्या 610 दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है :

“परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि से प्रभावित काश्तकारों/भू-स्वामियों के बावत लोक सुनवाई दिनांक 10 अप्रैल, 2023 को ग्राम—ताहिरपुर में हुई, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कार्यालय प्रभारी भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण वाराणसी, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत ताहिरपुर व प्रभावित काश्तकार/भू-स्वामी उपस्थित रहें। लोक सुनवाई में विस्थापन से प्रभावित होने वाले परिवारों द्वारा ग्राम पंचायत ताहिरपुर में आवास निर्माण हेतु भूमि की मांग की गयी व सहमति दी गयी की आवास हेतु भूमि उपलब्ध होने पर भूमि अर्जन से उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, जिसके क्रम में ग्राम ताहिरपुर में आराजी सं0 22/7 को चिन्हित कर प्रभावित परिवारों का आवास निर्माण हेतु प्रत्येक परिवार को 0.010 हे0 भूमि आवण्टित कर दी गयी है”

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी,
चन्दौली।

DEPARTMENT OF INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA VARANASI
FORM-19

[Sub-rule (1) of rule 27]

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 19 OF THE ACT]

NOTIFICATION

April 25, 2023

No. 1510/VIII-S.L.A.O.(S.S.)/Varanasi--Whereas preliminary notification No. 610 dated 14.10.2022 was issued under sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation Act, 2013, in respect of 25.58628 hectares of land in Village-Tahirpur and Milkipur, Pargana-Ralhupur, Tehsil-Pt. Deendayal Upadhyay Nagar, District-Chandauli is required for the public purpose, Inland Waterways Authority of India, Ministry of Ports, Shipping and Waterways required by the Government of India for public purpose such as Freight Village Project. The Deputy Collector Pandit Deendayal Upadhyay Nagar Chandauli was appointed Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the Section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under Section 19 (1) of the Act, that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public Village-Tahirpur and Milkipur, Pargana-Ralhupur, District-Chandauli, as given in schedule "B" has been identified as the rehabilitation and resettlement area for the purpose of rehabilitation and resettlement of the displaced families.

The Governor is further pleased under sub-section (2) as section 19 of the Act, to direct the Collector of Chandauli to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectares</i>
Chandauli	Pandit Dindayal Upadhyay Nagar	Ralhupur	Tahirpur	1 / 1	0.0510
				2 / 1	0.5940
				2 / 2	0.2460
				2 / 69 mi	0.0124
				2 / 69 mi	0.0114
				2 / 69 mi	0.0164
				2 / 69 mi	0.0124
				2 / 69 mi	0.0114
				2 / 69 mi	0.0115
				3	0.0400
				4	0.1740
				5 / 1 mi	0.0590
				5 / 1 mi	0.0201
				5 / 1 mi	0.0570
				5 / 1 mi	0.0570
				5 / 1 mi	0.0590
				5 / 1 mi	0.0590
				5 / 1 mi	0.0590
				5 / 2 mi	0.3277
				5 / 3	0.0810
				5 / 4 mi	0.0650
				5 / 4 mi	0.7820
				5 / 4 mi	0.7430
				5 / 4 mi	0.1300

1	2	3	4	5	6
					<i>Hectares</i>
Chandauli	Pandit Dindayal Upadhyay Nagar	Ralhupur	Tahirpur	5/4 mi	0.1537
				5/4 mi	0.6480
				5/9 mi	0.2630
				5/10 mi	0.1067
				5/10 mi	0.1067
				5/11 mi	0.0714
				5/11 mi	0.0714
				5/12 mi	0.3640
				5/5 mi	0.0966
				5/6 mi	0.0696
				5/6 mi	0.0696
				5/7 mi	0.1164
				5/7 mi	0.1164
				5/8 mi	0.5260
				6 mi	0.0410
				6 mi	0.0380
				6 mi	0.0390
				6 mi	0.0380
				6 mi	0.0380
				6 mi	0.0390
				6 mi	0.0380
				10 mi	0.0099
				10 mi	0.1187
				10 mi	0.1187
				10 mi	0.5474
				10 mi	0.1516
				24 mi	0.0330
				24/1 mi	0.0950
				24/1 mi	0.1250
				24/1 mi	0.0500
				24/1 mi	0.6683
				24/1 mi	0.0160
				24/1 mi	0.0294

1	2	3	4	5	6
					<i>Hectares</i>
Chandauli	Pandit Dindayal Upadhyay Nagar	Ralhupur	Tahirpur	24 / 1 mi	0.2216
				24 / 2 mi	0.3985
				24 / 2 mi	0.1530
				24 / 2 mi	0.0840
				24 / 3	0.0260
				24 / 3 mi	0.0342
				25 mi	0.0650
				25 mi	0.0200
				25 mi	0.0200
				26 mi	0.0350
				26 mi	0.2340
				27 mi	0.1050
				27 mi	0.0140
				28 mi	0.2010
				28 mi	0.0300
				29 / 1 mi	0.0080
				29 / 1 mi	0.0290
				29 / 2 mi	0.0360
				30	0.0080
				32 / 2	0.0650
				32 / 3	0.2630
				33	0.0610
				33 mi	0.1740
				34	0.0890
				35	0.2390
				36 mi	0.0740
				36 mi	0.1130
				36 mi	0.1130
				36 mi	0.0400
				37 mi	0.1500
				38	0.2390
				40	0.1380
				41 mi	0.1200
				41 mi	0.3200

1	2	3	4	5	6
					<i>Hectares</i>
Chandauli	Pandit Dindayal Upadhyay Nagar	Ralhupur	Tahirpur	41 mi	0.0890
				41 mi	0.2280
				42/1 mi	0.0360
				46 mi	0.1450
				46 mi	0.4550
				47 mi	0.0530
				47 mi	0.4750
				47 mi	0.0930
				47 mi	0.0560
				47 mi	0.0700
				47 mi	0.0530
				48 mi	0.0310
				48 mi	0.0930
				48 mi	0.1540
				49 mi	0.0600
				49 mi	0.1420
				49 mi	0.0250
				49 mi	0.1660
				49 mi	0.0400
				54	0.1540
				55 mi	0.1130
				55 mi	0.0960
				55 mi	0.1710
				55 mi	0.0120
				55 mi	0.0830
				55 mi	0.0890
				56 mi	0.0210
				56 mi	0.0080
				56 mi	0.0600
				56/2 mi	0.0040
				57/1 mi	0.0280
				57/2 mi	0.0050
				Total . .	15.9211

1	2	3	4	5	6
					<i>Hectares</i>
Chandauli	Pandit Dindayal Upadhyay Nagar	Ralhupur	Milkipur	8 / 1	0.01500
				8 / 3	0.01343
				9 / 1 mi	0.06400
				9 / 1 mi	0.02000
				10 / 2	0.15980
				10 / 3	0.13400
				11	0.09300
				12	0.29500
				13 mi	0.10800
				13 mi	0.10800
				13 mi	0.21600
				14	0.08100
				15	0.01200
				16	0.40100
				17	0.16200
				17 / 77	0.19000
				18	0.04000
				19 mi	0.39784
				20	0.21977
				21 / 2	0.08680
				22	0.02256
				23 mi	0.01200
				23 / 1 mi	0.02800
				23 / 3	0.09880
				24 / 1 mi	0.18163
				24 / 2	0.04900
				25	0.23178
				27 / 3	0.47270
				27 / 2	0.01500
				27 / 4 mi	0.07700
				27 / 5	0.06070
				27 / 6	0.27500
				28	0.51400
				29	0.36800
				30 / 1 mi	0.06710
				30 / 2	0.02690
				32 mi	0.05200
				32 mi	0.05290
				32 mi	0.22400
				33 mi	0.09700
				34 mi	0.02131
				34 mi	0.01350

1	2	3	4	5	6
					<i>Hectares</i>
Chandauli	Pandit Dindayal Upadhyay Nagar	Ralhupur	Milkipur	34 mi	0.01350
				35	0.18280
				36	0.06500
				37 mi	0.00100
				38	0.09300
				39	0.03036
				40	0.13400
				41	0.01200
				42	0.02400
				43	0.00400
				44	0.06900
				45	0.09700
				46	0.15800
				47	0.19000
				48 mi	0.27500
				48 mi	0.04000
				48 mi	0.06100
				49	0.14070
				54	0.12900
				56	0.06500
				57 / 1	0.15400
				57 / 2 mi	0.06650
				57 / 2	0.10900
				61	0.26920
				62 / 1	0.10100
				62 / 2	0.10900
				63 / 2	0.26300
				62 / 3	0.00540
				64	0.09300
				65	0.13820
				66	0.04000
				67	0.17320
				68	0.14600
				70	0.42780
				75	0.00800
				Total . .	9.66518

SCHEDULE-B

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be earmarked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectares</i>
Chandauli	Pandit Dindayal Upadhyay Nagar	Ralhupur	Tahirpur	22 / 7	0.1500

NOTE-A plan of land taken up for such acquisition can be seen in the Office of the Collector, Chandauli.

NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR

(Under Sub-section (2) of Section 19 of the Act)

By the order of declaration made under Government notification no. 610 dated 14.10.2022 for 25.58628 hectares of land in Village-Tahirpur and Milkipur, Pargana-Ralhupur, Tehsil- Pandit Dindayal Upadhyay Nagar, District-Chandauli is required for public purpose namely Freight Village, through Inland Waterways Authority of India, Ministry of Ports, Shipping and Waterways. I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification a summary of the Rehabilitation and Resettlement given below :

"A public hearing was held on 10.04.2023 at Village-Tahirpur, in which Tehsildar, Naib Tehsildar, Office in-charge of Inland Waterways Authority of India Varanasi, Village Head, Gram Panchayat Tahirpur, land owners affected through proposed land for the project were present. In the public hearing, the families affected by the displacement demanded land for construction of houses in Gram Panchayat Tahirpur and they agreed that they would not have any objection to the acquisition of land for project. In continuation with it, each affected family was allocated 0.010 hectares of land (Total land 0.1500 hectares) demarcated in Village Tahirpur at Plot No. 22/7 for the construction of houses (Rehabilitation and Resettlement).

NOTE: A plan of land taken up for such acquisition can be seen in the Office of the Collector, Chandauli.

(Sd.) ILLEGIBLE,
Collector, Chandauli.

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति**पर्यटन विभाग**

प्रारूप-18

[नियम-20 का उपनियम (2)]

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

27 अप्रैल, 2023 ई0

सं0 1524/आठ-वि0भू0अ0अ0 (सं0सं0) वाराणसी-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन जनपद-वाराणसी के सुनियोजित विकास हेतु उ0प्र0 सरकार/कलेक्टर की राय है, जनपद-वाराणसी में ग्राम-सीरगोवर्धनपुर, परगना-देहात अमानत, तहसील-सदर, वाराणसी के अन्तर्गत संत श्री रविदास जी की जन्मस्थली के पर्यटन विकास हेतु, ग्राम-सीरगोवर्धनपुर व जिला-वाराणसी में 0.6948 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2-सामाजिक समाघात निर्धारण एजेंसी मेसर्स ई0एन0वी0 डेवलपमेन्टल असिस्टेन्स सिस्टम (इण्डिया) प्राईवेट लि0 लखनऊ द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी। जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2023 को अनुमोदित किया गया है।

3-भूमि अर्जन के कारण प्रश्नगत ग्राम में कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा।

4-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0-414/एक-13-2014-7क(8)/2014 लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2014 के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी, सदर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं :-

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
वाराणसी	सदर	देहात अमानत	सीरगोवर्धनपुर	581	हेक्टेयर 0.0240
				588 / 1	0.0120
				590	0.0096
				591	0.0125
				592	0.1245
				593	0.2463
				594	0.1532
				595	0.0275
				596	0.0276
				599	0.0096
				600	0.0360
				765	0.0120
				योग .	0.6948

6-अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7-अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर, वाराणसी को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8-अधिनियम की धारा-11(4) के अंतर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर, वाराणसी के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी:—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, वाराणसी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
वाराणसी।

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE
GOVERNMENT/COLLECTOR [UNDER SUB-SECTION (1) OF
SECTION 11 OF THE ACT, 2013]
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
TOURISM DEPARTMENT
FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]
NOTIFICATION

April 27, 2023

No. 1524/VIII-S.L.A.O. (S.S.) Varanasi—Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector for the purpose of Development of the Tourism at Village Seer Goverdhanpur, District Varanasi is satisfied that a total of 0.6948 hectares of land is required in the Village Seer Goverdhanpur, Pargana Dehat Amanat, Tehsil Sadar, District Varanasi.

2—Social Impact Assessment study was carried out by M/s. E.N.V. Development Assistance System (I) Pvt. Ltd. C-363, Indra Nagar, Lucknow and it has submitted its recommendations to the Appropriate Government Agency which has approved its recommendations on dated 04-03-2023.

3—Due to land acquisition no family is being displaced in the said village.

4—In the sequence of Government Order No. 0-414/One-13-2014-7A(8)/2014 Lucknow dated 06 August, 2014, issued by the Government of Uttar Pradesh, The Sub-Divisional Officer, Sadar is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the affected families.

5—Therefore, the Governor is pleased to accept and notify for general information that land mentioned in the Schedule given below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
Varanasi	Sadar	Dehat Amanat	Seer Goverdhanpur	581	0.0240
				588/1	0.0120
				590	0.0096
				591	0.0125
				592	0.1245
				593	0.2463
				594	0.1532
				595	0.0275
				596	0.0276
				599	0.0096
				600	0.0360
				765	0.0120
				Total . .	0.6948

6—The Hon'ble Governor is also pleased to authorize the Collector, District Varanasi for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon, conduct survey of land, take levels of any land, dig into the sub-soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7—Under section 15 of the Act, any person whose interest lies in the land in question may within a period of 60 days after the publication of this notification, make an objection on acquisition of land in the locality in writing to the Collector, Varanasi.

8—Under section 11(4) of the Act, no person without prior approval of the Collector, Varanasi shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/ purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed.

NOTE—A plan of land taken up for such acquisition can be seen in the Office of the Collector, Varanasi.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Varanasi.

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर

28 अप्रैल, 2023 ई०

शुद्धि-पत्र

सं० 1849/आठ-वि०भू०अ०अ०अ०—उत्तर प्रदेश गजट 22 अप्रैल, 2023 ई० (बैशाख 02, 1945 शक संवत्) के भाग 1-क के पेज नं० 441 के पैरा-7 के (हिन्दी) में प्रकाशित कलेक्टर, सोनभद्र के स्थान पर कलेक्टर, मीरजापुर एवं पेज नं० 441 पैरा-7 के (अंग्रेजी) में प्रकाशित Collector, Sonbhadra के स्थान पर Collector, Mirzapur पढ़ा जाय।

ह० (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पी०एस०यू०पी०—6 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2023 ई०।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ०प्र०, प्रयागराज।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 06 मई, 2023 ई० (बैशाख 16, 1945 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क-नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख-नगर पंचायत,
खण्ड-ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ-जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत, सहारनपुर

31 मार्च, 2023 ई०

सं० 4085/एल०बी०सी०/2022-23-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (1994) की धारा-239 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए जिला पंचायत सहारनपुर के अधीन बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण कार्यों को नियन्त्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से जिला पंचायत, सहारनपुर द्वारा शासकीय गज़ट के प्रकाशनार्थ निम्नवत उपविधि बनायी गयी है:-

उपविधि

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-239 (1) एवं धारा-239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा-143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत, सहारनपुर ने ग्राम्य क्षेत्र, जो कि उक्त अधिनियम की धारा-2 (10) में परिभाषित है, में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-2 (डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियन्त्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधियां बनायी गयी हैं।

1-“अधिनियम” का तात्पर्य उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है।

2-“ग्राम्य क्षेत्र” से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद्, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जो कि किसी विकास प्राधिकरण या यू०पी०एस०आई०डी०सी० के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम्य का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गज़ट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

3-“विनियमन” का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4-“मानचित्र” से तात्पर्य भवन के ड्राईंग, डिजाईन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है जो कि पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किय गया हो एवं डिजाइन योग्य (Elegible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

5-“निर्माण कार्य” का तात्पर्य किसी भवन में निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6-“भवन की ऊँचाई” का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊँचे बिन्दु तक नापी गई लम्बवत् पर (Vertical) ऊँचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊँचाई में मम्टी, मशीन रूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊँचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7-“छज्जा” का तात्पर्य ऐसी ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जो कि सामान्यतः सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8-“ड्रेनेज” का तात्पर्य उस, व्यवस्था से है, जिसका निर्माण कसी तरल पदार्थ जैसे- रसोई, स्नानगृह से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित है।

9-“निर्मित भवन” का तात्पर्य ऐसे भवन से है जो कि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।

10-“तल” (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खण्ड से है जहाँ पर सामान्यतः किसी भवन में चला फिरा जाता हो।

11-“फ्लोर एरिया रेशियो” (FAR) का तात्पर्य उस भागफल से है जो सभी तलों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने पर प्राप्त होता है।

12-“भू-आच्छादन” (Ground Coverage) का तात्पर्य भू-तल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से है।

13-“ग्रुप हाउसिंग” का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हो तथा मूल सुविधाओं जैसे- पार्किंग, पार्क, बाजार जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो।

14-“ले-आउट” प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है जो कि किसी स्थल के समस्त भू-खण्ड, भवन खण्ड, मार्ग खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भू-निर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाला प्लान से है।

15-प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है-

(अ) अभियन्ता-अभियन्ता, जिला पंचायत, सहारनपुर से है।

(ब) अवर अभियन्ता-इस उपविधि में अवर अभियन्ता का तात्पर्य उस अवर अभियन्ता से है जिसको अभियन्ता जिला पंचायत द्वारा भवन के नक्शों की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निर्देशित (Designated) किया गया हो।

16-“कार्य अधिकारी” का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत, सहारनपुर से है।

17-“अधिभोग” (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18-“स्वामी” का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

19-“रेन वाटर हार्वेस्टिंग” का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू-गर्भ जल के स्तर को ऊँचा उठाने से है।

20—“सेटबैक” का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथा स्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गई खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21—“अपर मुख्य अधिकारी” का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सहारनपुर से है।

22—“जिला पंचायत” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17(1) में संघटित जिला पंचायत, सहारनपुर से है।

23—“अध्यक्ष” का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, सहारनपुर से है।

24—बहु मंजिला भवन (Multystory) चार मंजिला अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का भवन बहु मंजिला कहलायेगा।

25—“मंजिल” का तात्पर्य भवन के उस भाग से है जो किसी तल की सतह और इसके ऊपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल न हो तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हो।

26—“भवन” का तात्पर्य ऐसी स्थाई प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है जो किसी भी प्रकार की सामाग्री से निर्माण किया जाये एवं उसका प्रत्येक भाग चाहे मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लेटफार्म, बरामदा, बालकनी, कार्नर या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टेन्ट, शामियाना, तिरपाल आदि जो कि पूर्णतः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिए लगाये जाते हैं, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

27—आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल हैं।

28—व्यवसायिक/वणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण बाजार, व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप होटल, पेट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधाएं जो माल व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हो, सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

29—संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामाग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्यधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रसायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कारोसिव गैसें पैदा होती हों या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामाग्री या जिनके परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-छोटे कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण, वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिए प्रस्तुत किया जाता हों।

30—भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

31—“पार्किंग स्थल” का तात्पर्य ऐसे चहारदीवारी में बंद या खुले स्थान से है जहाँ पर वाहन इकट्ठे रूप में खड़े हो सकते हैं, परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं हैं, का तात्पर्य वही होगा जोकि ऐसे शब्दों का (National building code), एवं (Bureau of Indian standards) यथासंशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभास की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।

उपविधि

ये उपविधियां जिला पंचायत, सहारनपुर के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जो कि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार, कम्पनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाइटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाउसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले-आउट प्लान एवं/या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी।

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा।

1—उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगा—

(अ) ये उपविधियां कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी की शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊँचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होंगी परन्तु सुरक्षित डिजाइन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को एक लिखित सूचना देनी होगी।

(ब) सफेदी व रंग-रोगन के लिए।

(स) प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए।

(द) पूर्व स्थान पर छत पुनर्निर्माण के लिए।

(य) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निर्माण।

(र) मिट्टी खोदने या मिट्टी से गड़ढा भरना।

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तार भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनाएं प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा—

1—स्थल का नक्शा निम्नवत् दिया जायेगा—

(i) ले-आउट प्लान का पैमाना 1: 500 होगा।

(ii) की-प्लान का पैमाना 1: 1000 होगा।

(iii) बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1: 100 होगा।

(iv) स्थल के चारों तरफ की सीमाएं उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम।

(v) समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी।

(vi) स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे— विक्रय आलेख, दाखिल खारिज, खतौनी आलेख।

2—प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा।

(अ) प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित।

(ब) नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद का पंजीकरण नम्बर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(स) नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर ।

(य) भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिए प्रार्थना-पत्र ।

(र) भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे— आवासीय, व्यावसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन ।

(ल) स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊँचाई, सेक्सन स्ट्रक्चर विवरण, रैन हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेन्ट, लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लांट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था, अग्नि निकास जीने की स्थिति व अन्य विवरण ।

(व) नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता ।

(स) नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउंड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण ।

3—बहुमंजिली भवन (Multy Story) चार मंजिल अथवा 15 मी० से अधिक ऊँचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी ।

4—अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था, आपात सीढ़ी व निकासी, अग्नि सुरक्षा लिफ्ट अग्नि अलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location)

5—निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियां आदि ।

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियां

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि—

(अ) प्रस्तावित भवन का उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न हैं ।

(ब) प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उसमें किसी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हों ।

(स) प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनाएं भड़काने का स्रोत (Source of Annouyance) अथवा आस-पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो ।

(घ) तकनीकी अनुदेश (Technacal Instructions)

1—(क) एक आवास गृह में 4.5 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है ।

(ख) भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मी० ऊँचाई तक अनुमन्य होगी ।

(ग) लिंगल (Lintel) अथवा छत पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मी० एवं 0.76 मी० चौड़ा होगा ।

(घ) बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जायेगा । बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊँचाई 4.5 मी० तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम ऊँचाई 1.5 मी० होगी । स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लॉट से 2.00 मी० दूरी तक निर्मित किया जा सकता है ।

(ङ) बहुमंजिली भवन में कम से कम एक सामान (Goods) मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा ।

(च) राष्ट्रीय भवन संहिता (Natioanl building code) 2005 के प्रावधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मी० से 16.0 मी० की दूरी होगी । भवन की 18.0 मी० ऊँचाई तक 6.0 मी० इसके पश्चात् प्रत्येक

3.0 मी0 अतिरिक्त ऊँचाई के लिए ब्लाक की दूरी 1.0 मी0 बढ़ाई जायेगी। भू-खण्ड के डैड एन्ड (Dead End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9.0 मी0 होगी।

(छ) बहुमंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्राविधान किया जा सकता है सेवा तल की अधिकतम ऊँचाई 2.4 मी0 होगी।

2-निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिए भू-खण्ड का 10 प्रतिशत क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है।

(क) जनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्डरूम, टॉयलेट ब्लाक, ड्राइवर रूम, विद्युत् उपकेन्द्र आदि।

(ख) मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।

(ग) ढके हुए पैदल पथ आदि।

3-(क) आवासीय भवन में कमरे का आकार 2.4 मी0 एवं 9.5 वर्ग मी0 से कम न होना चाहिए।

(ख) छत की सीलिंग की ऊँचाई 2.75 मी0 से कम न होनी चाहिए।

(ग) ए0सी0 कमरे की ऊँचाई 2.40 मी0 से कम न होनी चाहिए।

(घ) रसोई घर की ऊँचाई 2.75 मी0 आकार 1.80 मी0 एवं 5.00 वर्ग मी0 से कम न होना चाहिए।

(ङ) संयुक्त संडास (TOILET) का आकार 1.20 मी0 एवं 2.20 वर्गमी0 से कम न होना चाहिए।

(च) खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत से कम न होना चाहिए।

(छ) तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.00 मी0 एवं इससे अधिक ऊँचे भवन में 1.50 मी0 से कम न होनी चाहिए।

4-(क) पार्क, टोट-लोट्स (Tot-Lots) लैंडस्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।

(ख) 30 मी0 तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रंट सेट-बैक के योग का डेढ़ गुना होगी।

(ग) भू-कम्प रोधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी।

5-स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी जिला पंचायत, का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा।

6-बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील विस्फोटक सामाग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

(ङ) रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मी0 के भू-आच्छादन (GROUND COVERAGE) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्ग मी0 के भू-आच्छादन (GROUND COVERAGE) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(च) विकसित जनपदों की सूची

लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर एवं झांसी।

(छ) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियों (FAR)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर रेशियों (FAR) के मानक निम्नवत होंगे—

क्र० सं०	भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन प्रतिशत	फ्लोर एरिया रेशियों (FAR)	भवन की अधिकतम ऊँचाई सूची (1) के अनुसार जनपदों में	भवन की अधिकतम ऊँचाई अन्य जनपदों में
1	2	3	4	5	6
				मीटर	मीटर
1	(i). आवासीय भवन-भू-खण्ड 500 वर्ग मी० तक	80	3.00	15	15
	(ii). आवासीय भवन भू-खण्ड 500-2,000 वर्ग मी० तक	65	4.00	15	15
2	ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	30	21
3	औद्योगिक भवन	60	1.00	18	12
4	व्यवसायिक भवन—				
	(i) सुविधा (Convenient) शापिंग केन्द्र शापिंग माल्स, व्यवसायिक केन्द्र, होटल	40	2.50	30	21
	(ii) बैंक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	40	1.50	24	18
	(iii) वेयर हाउस, गोदाम	60	1.50	18	15
	(iv) दुकानें व मार्केट	60	1.50	15	10
5	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन—				
	(i)—सभी उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कालेज आदि।	50	1.50	24	15
	(ii)—हायर सेकेंडरी, प्राइमरी, नर्सरी, स्कूल, क्रेच, सेन्टर आदि।	50	1.50	24	15
	(iii)—हॉस्पिटल, डिस्पेन्सरी, चिकित्सालय लैब, नर्सिंग होम आदि।	75	2.50	24	15
6	धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन—				
	(क) सामुदायिक केन्द्र, क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन, केन्द्र डाकघर, पुलिस स्टेशन	50 30	1.20 1.50	15 15	10 10
	(ख) धर्मशाला, लॉज, अतिथि गृह, हास्टल	40	2.50	15	10
	(ग) धर्मकांटा, पेट्रोलपम्प, गैस गोदाम, शीतगृह	40	0.50	10	6
7	कार्यालय भवन—				
	सरकारी, अर्द्धसरकारी, कॉर्पोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन	40	2.00	30	15
8	क्रीडा एवं मनोरंजन काम्प्लेक्स, सूटिंग रेंज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	20	0.40	15	10
9	नर्सरी	10	0.50	6	6
10	बस स्टेशन, बसडिपो कार्यालया	30	2.00	15	12
11	फार्म हाउस	10	0.15	10	6
12	डेरी फार्म	10	0.15	10	6
13	मुर्गा, सुअर, बकरी फार्म	20	0.30	6	6
14	ए०टी०एम०	100	1.00	6	6

(ज) सेट बैक (Set back)

क्र० सं०	भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	सामने (Front)	साईट (Side)	पीछे (Reer)	लैंड स्केपिंग (Land scaping)	खुला स्थान तक
1	2	3	4	5	6	7
		मीटर	मीटर	मीटर		प्रतिशत
1	150 तक	3.0	0.0	1.5	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मी०	25
2	151—300	3.0	0.0	3.0		25
3	301—500	4.5	3.0	3.0		25
4	501—2000	6.0	3.0	3.0		25
5	2001—6000	7.5	4.5	6.0		25
6	6001—12000	9.0	6.0	6.0		25
7	12001—20000	12.0	7.5	7.5		50
8	20001—40000	15.0	9.0	9.0		50
9	40001 से अधिक	16.0	12.0	12.0		50

(झ) पार्किंग स्थान

क्र०सं०	भवन/भू-खण्ड	पार्किंग स्थल
1	2	3
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक (ECU) प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत एवं भौक्षणिक भवन	एक (ECU) प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक (ECU) प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
4	व्यावसायिक भवन	एक (ECU) प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	एक (ECU) प्रति 50 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लॉज, अतिथि गृह, हॉस्टल	एक (ECU) प्रति 2 अतिथि रुम के लिए
7	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम	एक (ECU) प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR)का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक (ECU) प्रति 15 सीट्स
9	आवासीय भवन	एक (ECU) प्रति 150 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR)का

(ज) अग्नि शमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसेज

1—तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा-संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन व्यवसायिक भवन, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सिनेमा मल्टीप्लेक्स 400 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकाश हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारों तरफ बाउन्ड्री के दीवार के साथ-साथ 6 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा। जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4.0 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carrage way) होगा।

2-अग्नि निकास जीने के न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मी0 ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 सेमी0 राईजर अधिकतम 19 सेमी0 एक फ्लाइंट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

3-अग्नि निकास जीने तक पहुंच दूरी 15 मी0 से अधिक न होनी चाहिए।

4-घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों में नहीं किया जायेगा।

5-उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

6-उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (NATIONAL BUILDING CODE) 2005 भाग-4 के अनुसार प्रावधान किया जायेगा जैसे- स्वचालित स्प्रिंकलर पद्धति, फर्स्ट एण्ड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्गों के संकेत चिन्ह, फायर मैन, स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेंट राइजर डाउन कर्नर सिस्टम आदि।

(ट) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी

क्रमांक	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी	क्षैतिज दूरी
1	2	3	4
		मीटर	मीटर
1	लो एंड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाईन-33000 वोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, लाईन	$3.7 + (0.305 \text{ मी0})$ प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	$1.8 + (0.305 \text{ मी0})$ प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

(ठ) मोबाइल टावर्स की स्थापना

(क) मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

(ख) जनरेटर केवल 'साईलेंट' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाये जायेंगे।

(ग) यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिए।

(घ) जहां अपेक्षित हो, वहां टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ङ) सेवा आपरेटर कम्पनी और भवन स्वामी को संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बन्धित कम्पनी और भवन स्वामी का होगा।

(च) इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो विकिरण, वायुब्रेसन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(छ) अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए सूची (1) के अनुसार जनपदों में प्रथम बार शुल्क के रूप में एक लाख रुपये व अन्य जनपदों में पचास हजार रुपये जिला पंचायत में जमा कराने होंगे। यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा अप्रत्यापणीय (Non-refundable) होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार की शुल्क का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष जमा कराने होंगे।

(ज) शैक्षणिक संस्था, हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती अथवा धार्मिक भवन स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी।

(ड) नक्शे स्वीकृति की दरें

(क) आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन—

सूची (I) के अनुसार जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर 50 रुपये प्रति वर्गमीटर, अन्य जनपदों में यह दर 25 रुपये प्रति वर्गमीटर होगी।

(ख) व्यवसायिक एवं व्यापारिक भवन—

सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रु0 50.00 प्रति वर्ग मीटर, अन्य मीटर होगी।

सूची (I) के अनुसार जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रु0 100.00 प्रति वर्गमीटर, अन्य जनपदों में यह दर रु0 50.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

(ग) (i)—भूमि की प्लॉटिंग—भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लॉटों में बांटना।

(ii)—भूमि विकास—भूमि को योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हाल आदि।

(iii)—भूमि का उपयोग—भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे—निर्माण सामग्री, कंटेनर, ईंधन आर0सी0सी0 पाईप आदि।

(iv)—किसी परियोजना का ले-आउट प्लान (तल-पट मानचित्र) उपरोक्त ग—(i) से (iv) तक सूची (iv) के अनुसार जनपदों में रु0 20.00 प्रति वर्ग मीटर, तथा अन्य जनपदों में यह दर रु0 10.00 प्रति वर्गमीटर होगी।

(घ) पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होंगी।

(ङ) स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होंगी।

(च) बेसमेंट, स्टिल्ट, पोजियम सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की अनुज्ञा शुल्क में गणना की जायेगी।

(छ) यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10 प्रतिशत होगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50 प्रतिशत होगी।

(ज) उपविधियों के अनुसार जिला पंचायत से नक्शे की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने अथवा जिला पंचायत भवन की उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थ-दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जायेगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20 प्रतिशत से अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरान्त पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा-248 में दी गई व्यवस्था से नियन्त्रित होगी।

(झ) सूची (I) के अनुसार जनपदों में पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें रु0 20.00 प्रति वर्गमीटर एवं अन्य जनपदों में रु0 10.00 प्रति वर्ग मीटर होगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होंगी।

(ण) सूची (I) के अनुसार जनपदों में बाउण्ड्री वाल स्वीकृति की दरें रु0 10.00 प्रति मीटर व्यय अन्य जनपदों में रु0 5.00 प्रति मीटर होगी।

नोट—(शुल्क निर्धारण हेतु भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी)।

(ण) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1—स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के कार्यालय में जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुतीकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2—ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3—कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।

4—कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियन्ता, जिला पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।

5—अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निर्देशित (Designated) अवर अभियन्ता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6—अवर अभियन्ता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियन्ता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।।

7—अवर अभियन्ता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरांत बहुमंजिली भवन, व्यावसायिक भवन, संकटमय-भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियन्ता, जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।

8—अभियन्ता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरांत सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शे की स्वीकृति हेतु अवर अभियन्ता से एक अंतरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आंगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरांत ही नक्शे के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9—जिला पंचायत के अभियन्ता द्वारा परियोजना की संभाव्यता (Possibility) सुगमता (Convenience) साध्यता (Feasibility) तकनीकी जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदन कर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10—अभियन्ता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाए जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियन्ता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) कराके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

11—अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग-पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिए एक माह का समय दिया जायेगा।

12—आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरांत अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। '

13—उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत आवेदक को अनुज्ञा-पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14—यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग-पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।

विवाद:—

उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत को सन्दर्भित किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश अभ्यर्थकों पर बन्धनकारी होगा।

(त) सामान्य अनुदेश (General Indtrutions)

1—भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। 200 मीटर से 1.5 किलोमीटर के दायरे में निर्माण की मंजिलों एवं ऊँचाई की अनुमति तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जायेगी।

2—भू-खण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

3—भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) वाहन पार्किंग बेसमेंट वाहन पार्किंग, भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव व सेवा तल (Service Floor) भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाए तो इनका क्षेत्रफल एफ0ए0आर0 में शामिल नहीं होगा।

4—निकटतम हवाई अड्डा चाहे विमानापत्तन प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो के 5.00 किमी० की परिधि में 30 मी० से ऊँचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

5—उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-आच्छादन, प्लोर एरिया रेशियो (FAR) अथवा अधिकतम ऊँचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6—उपरोक्त सूची में उल्लिखित, भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण, जिला पंचायत द्वारा इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7—मल्टी लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेंट अनुमन्य होंगे।

8—इन उपविधियों के आधीन अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।

9—इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सी०आर०पी०सी० की धारा 133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(थ) अनुज्ञा की शर्तें

अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरांत यदि यह संज्ञान में आये कि नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पंचायत द्वारा दी गई नक्शे की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है। किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal) किया जा सकता है।

(क) अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा कि वह अभियन्ता जिला पंचायत की संस्तुति पर, वास्तुविद् द्वारा प्रस्तुत नक्शे में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दे।

(ख) पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाईन वास्तुविद् के अन्तर्गत कार्य करने वाले योग्य अभियन्ता द्वारा कराया जायेगा।

(ग) कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(द) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1981 की धारा-240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, सहारनपुर यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन रु0 1,000.00 (एक हजार मात्र) तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 50.00 (पचास मात्र) प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो कि तीन माह तक हो सकेगा।

लोकेश एम0,
आयुक्त,
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

जिला पंचायत, कन्नौज

18 अप्रैल, 2023 ई0

सं0 1869/23-जि0 पं0-उपविधि/2023-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239 (1) एवं धारा 239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर के जिला पंचायत कन्नौज ने ग्राम्य क्षेत्र, जोकि उक्त अधिनियम की धारा 2 (10) में परिभाषित है, में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 2 (डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधियां बनायी है।

1-अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है।

2-ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जोकि किसी विकास प्राधिकरण या यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

3-विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4-मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाईन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जोकि पंजीकृत वास्तुविद् के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Elegible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

5-निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन में निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6-भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊंचाई में टंकी, मशीन रूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7-छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जोकि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8-ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नानगृह, से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित है।

9-निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जोकि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।

10-तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खंड से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला फिरा जाता हो।

11-फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) का तात्पर्य उस भागफल से है, जो सभी तलो के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12-भू-आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भू-तल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

13-ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय प्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हों तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क, बाजार, जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो।

14-ले-आउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जोकि किसी स्थल के समस्त भू-खण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भू-निर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाला प्लान से है।

15-प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है:-

अ-अभियंता-अभियंता, जिला पंचायत

ब-अवर अभियंता-इस उपविधि में अवर अभियंता का तात्पर्य उस अवर अभियंता से है जिसको अभियंता, जिला पंचायत द्वारा भवन के नक्शों की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निदेशित (Designated) किया गया हो।

16-कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत से है।

17-अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18-स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

19-रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भूगर्भ जल के स्तर को ऊंचा उठाने से है।

20-सेटबैक का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथा स्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21-अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत कन्वैज से है।

22—जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17(1) में संघटित जिला पंचायत कन्नौज से है।

23—अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत कन्नौज से है।

24—बहु मंजिली भवन (Multy Storey) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन बहु मंजिल कहलायेगा।

25—मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके उपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके उपर कोई तल न हों, तो वह स्थान जो तल और इसके उपर की छत के मध्य हों।

26—भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जोकि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जायें, एवं उसका प्रत्येक भाग चाहें मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लैटफार्म, बरान्डा, बालकनी, कार्नास या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टैन्ट, शामियाना, तिरपाल आदि जोकि पूर्णतः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिये लगाये जाते हैं, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

27—आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल है।

28—व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण बाजार व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप होटल, पेट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधाएं जो माल व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

29—संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्यधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कारोसिव गैसें पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-2 कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो।

30—भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

31—पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चारदीवारी में बंद या खुले स्थान से है, जहां पर वाहन इकट्ठे रूप में खड़े हो सकते हैं, परन्तु इसके लिए आवश्यक है, कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं हैं, का तात्पर्य वही होगा, जोकि ऐसे शब्दों का National Building Code एवं Bureau of Indian Standards यथा संशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभास की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।

उपविधि

ये उपविधियां जिला पंचायत कन्नौज के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जोकि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार कंपनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाऊसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले-आउट प्लान एवं/या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी।

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियाँ

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा ।

1—उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी ।

अ—ये उपविधियाँ कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्गमी० क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊँचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होंगी परन्तु सुरक्षित डिजाईन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को एक लिखित सूचना देनी होगी ।

ब—सफेदी व रंग-रोशन के लिए ।

स—प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए ।

य—पूर्व स्थान पर छत पुनर्निर्माण के लिए ।

र—प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निर्माण ।

व—मिट्टी खोदने या मिट्टी से गड़डा भरना ।

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तार या भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा ।

1—स्थल का नक्शा निम्नवत दिया जायेगा:—

ले-आउट प्लान का पैमाना 1 : 500 होगा ।

की-प्लान का पैमाना 1 : 1000 होगा ।

बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1 : 100 होगा ।

स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम ।

समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी ।

स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल खारिज, खतौनी आलेख ।

2—प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा ।

(अ) प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित

(ब) नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद का पंजीकरण नंबर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर ।

(स) नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर ।

(य) भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिये प्रार्थना-पत्र ।

(र) भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय, व्यवसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन

(ल) स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, पलोर-प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊँचाई, सेक्सन, स्ट्रक्चर विवरण, रैन हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेंट, लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लांट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था अग्नि निकास जीने की स्थिति व अन्य विवरण।

(व) नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता!

(स) नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउंड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

3—बहु मंजिली भवन (मल्टी स्टोरी) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी—

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था आपात सीढ़ी व निकासी, अग्निसुरक्षा लिफ्ट अग्नि-अलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location) !

निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियाँ आदि

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियाँ

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि—

अ—प्रस्तावित भवन-उपयोग अनुम्य भू-उपयोग से भिन्न है।

ब—प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हो।

स—प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनाएं भड़काने का स्रोत (Source of Annoyance) अथवा आसपास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो।

(घ) तकनीकी अनुदेश (Technical Instructions)

1—(क) एक आवास गृह में 4.5 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है।

(ख) भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मीटर ऊँचाई तक अनुमन्य होगी।

(ग) लिंटल (Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौड़ा होगा।

(घ) बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जाएगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊँचाई 4.5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम ऊँचाई 1.5 मीटर होगी स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लाट से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

(ङ) बहु मंजिली भवन में कम से कम एक सामान (Goods)/मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

(च) राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 के प्रावधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.0 मीटर ऊँचाई तक 6.0 मीटर इसके

पश्चात् प्रत्येक 3.0 मीटर अतिरिक्त ऊँचाई के लिए ब्लॉक की दूरी 1.0 मीटर बढ़ाई जाएगी। भू-खण्ड के डैड एन्ड (Dead End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9.0 मीटर होगी।

(छ) बहु मंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है सेवा तल की अधिकतम ऊँचाई 2.4 मीटर होगी।

2—निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिये भू-खण्ड का 10% क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है।

क—जेनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक, ड्राईवर रूम, विद्युत उप केन्द्र आदि।

ख—मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।

ग—ढके हुए पैदल पथ आदि।

3—(क) आवासीय भवन में कमरे का आकर 2.4 मीटर एवं 9.5 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(ख) छत की सीलिंग की ऊँचाई 2.75 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(ग) ऐंसी० कमरे की ऊँचाई 2.40 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(घ) रसोई घर की ऊँचाई 2.75 मीटर, आकर 1.80 मीटर एवं 5.00 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(ङ) संयुक्त संडास (Toilet) का आकर 1.20 मीटर एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(च) खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10% से कम न होना चाहिए।

(छ) तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.00 मीटर एवं इससे अधिक ऊँचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए।

4—(क) पार्क, टोट-लोट्स (Tot-Lots), लैंड स्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15% होगा।

(ख) 30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रंट सेट-बैक के योग का डेढ़ गुना होगी।

(ग) भू-कम्प रोधी व सुरक्षित डिजाइन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाइनर की होगी।

5—स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा सवय की जायेगी जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा।

6— बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

(ङ) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(च) विकसित जनपदों की सूची (1)

लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, हापुड, शामली, मुजफ्फरनगर, एवं झांसी।

(छ) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के मानक निम्नवत होंगे

क्रमांक	भवन एवं भू-उपयोग	भू- आच्छादन प्रतिशत	फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)	भवन की अधिकतम ऊँचाई सूची (I) के अनुसार जनपदों में	भवन की अधिकतम ऊँचाई अन्य जनपदों में
1	2	3	4	5	6
				मीटर	मीटर
1	(i) आवासीय भवन भू-खण्ड 500 वर्ग मीटर तक	80	3.00	15	15
	(ii) आवासीय भवन भूखंड 500–2000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15	15
2	ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	30	21
3	औद्योगिक भवन	60	1.00	18	12
4	व्यावसायिक भवन—				
	(i) सुविध (Convenient) शॉपिंग केन्द्र, शॉपिक माल्स, व्यावसायिक केन्द्र, होटल	40	2.50	30	21
	(ii) बैंक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स,	40	1.50	24	18
	(iii) वेयर हाउस गोदाम,	60	1.50	18	15
	(iv) दुकाने व मार्केट	60	1.50	15	10
5	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन—				
	(i) सभी उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कॉलेज आदि	50	1.50	24	15
	(ii) हायर सेकंडरी, प्राईमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेंटर	50	1.50	24	15
	(iii) हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिंग होम आदि	75	2.50	24	15
6	धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन—	50	1.20	15	10
(i)	समुदायिक केंद्र क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन केंद्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	15	10
(ii)	धर्मशाला, लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	40	2.50	15	10
(iii)	धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीत गृह	40	0.50	10	6

1	2	3	4	5	6
				मीटर	मीटर
7	कार्यालय भवन—				
	सरकारी, अर्धसरकारी, कॉर्पोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन	40	2.00	30	15
8	क्रीडा एवं मनोरंजन कॉम्प्लेक्स, शूटिंग रेंज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केंद्र	20	0.40	15	10
9	नर्सरी	10	0.50	6	6
10	बस स्टेशन, बसडिपो, कार्यशाला	30	2.00	15	12
11	फार्म हाउस	10	0.15	10	6
12	डेरी फार्म	10	0.15	10	6
13	मुर्गा, सूअर, बकरी फार्म	20	0.30	6	6
14	ए०टी०एम०	100	1.00	6	6

(ज) सेट बेक (Set Back)

क्रमांक	भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	समने (Front)	साईड (Side)	पीछे (Rear)	लैंड स्केपिंग (Landscaping)	खुला स्थान तक
1	2	3	4	5	6	7
		मीटर	मीटर	मीटर		प्रतिशत
1	150 तक	3.0	0.0	1.5	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर	25
2	151-300	3.0	0.0	3.0	तथैव	25
3	301-500	4.5	3.0	3.0	तथैव	25
4	501-2000	6.0	3.0	3.0	तथैव	25
5	2001-6000	7.5	4.5	6.0	तथैव	25
6	6001-12000	9.0	6.0	6.0	तथैव	25
7	12001-20000	12.0	7.5	7.5	तथैव	50
8	20001-40000	15.0	9.0	9.0	तथैव	50
9	40001 से अधिक	16.0	12.0	12.0	तथैव	50

(झ) पार्किंग स्थान

क्रमांक	भवन/भू-खण्ड	पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक ECU प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
4	व्यावसायिक भवन	एक ECU प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक केंद्र	एक ECU प्रति 50 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	एक ECU प्रति 2 अतिथि रुम के लिए
7	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम	एक ECU प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक ECU प्रति 15 सीट्स
9	टावासीय भवन	एक ECU प्रति 150 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का

(ज) अग्नि शमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसिस

(i) तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा-संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन व्यावसायिक भवन हॉस्पिटल, नर्सिंग होम सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे भवन के चारो तरफ बाउन्ड्री दीवार के साथ-साथ 6 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा। जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carriage Way) होगा।

(ii) अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 से०मी०, राईजर अधिकतम 19 से०मी०, एक फ्लाइंट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

(iii) अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15 मीटर से अधिक न होनी चाहिए।

(iv) घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों में नहीं किया जायेगा।

(v) उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

(vi) उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 भाग-4 के अनुसार प्रावधान किया जाएगा जैसे स्वचालित स्प्रिंकलर पद्धति, फर्स्ट एंड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राइजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि।

(ट) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी

क्रमांक	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी मीटर	क्षैतिज दूरी मीटर
1	लो एंड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाईन 33000 वोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन	3.7+(0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	1.8+(0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

(ठ) मोबाइल टावर की स्थापना

(क) मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

(ख) जनरेटर केवल 'साइलेंट' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाए जाएंगे।

(ग) यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिए।

(घ) जहाँ अपेक्षित हो, वहाँ टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ङ) सेवा ऑपरेटर कंपनी और भवन स्वामी को संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बंधित कंपनी और भवन स्वामी का होगा।

(च) इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्स, रेडियो विकिरण, वायुब्रेसन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(छ) अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिये सूची (I) के अनुसार जनपदों में प्रथम बार शुल्क के रूप में एक लाख रुपये व अन्य जनपदों में पचास हजार रुपये जिला पंचायत में जमा कराने होंगे! यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा अप्रत्यापणीय (Non-Refundable) होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार की शुल्क का 10% प्रति वर्ष जमा कराने होंगे।

(ज) शैक्षणिक संस्था, हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती, अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी।

(ड) नक्शे स्वीकृति की दरें

(क) आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन

सूची (I) के अनुसार जनपदों में—सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

(ख) व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन

सूची (I) के अनुसार जनपदों में—सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

(ग) (I) भूमि की प्लानिंग-भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लानों में बाँटना।

(II) भूमि विकास—भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हाल आदि।

(III) भूमि का उपभोग—भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे निर्माण सामग्री, कंटेनर, ईंधन आर०सी०सी०पाईप आदि !

(IV) किसी परियोजना का ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र)

उपरोक्त (ग) (I) से (IV) तक, सूची (I) के अनुसार जनपदों में रु0 20.00 प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर रु0 10.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

(घ) पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होंगी।

(ङ) स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होंगी।

(च) बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम, सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की, अनुज्ञा शुल्क में गणना की जाएगी।

(छ) यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10% होंगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50% होंगी।

(ज) उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने, अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थ-दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जाएगा ! समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20% से अधिकतम 50% अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरांत पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गयी व्यवस्था से नियन्त्रित होगा।

(झ) सूची (1) के अनुसार जनपदों में पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर एवं अन्य जनपदों में 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर होंगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होंगी।

(ण) सूची (1) के अनुसार जनपदों में बाउन्ड्री वाल स्वीकृति की दरें 10 रुपये प्रति मीटर व्यय अन्य जनपदों में 5 रुपये प्रति मीटर होगी।

नोट—(शुल्क निर्धारण हेतु, भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी)

(ण) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1—स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के कार्यालय में जमा किये जायेंगे। एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2—ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3—कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।

4—कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियंता, जिला पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।

5—अभियंता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निदेशित (Designated) अवर अभियंता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6—अवर अभियंता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियंता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

7—अवर अभियंता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यवसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियंता जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।

8—अभियंता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरांत सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियंता से एक अंतरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आंगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शों के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंध यह है, कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग-पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है, तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी। अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9—जिला पंचायत के अभियंता द्वारा परियोजना की संभाव्यता (Possibility), सुगमता (Convenience), साध्यता (Feasibility), तकनीकी जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदन कर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10—अभियंता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियंता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) कराके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

11—अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियंता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग-पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिये एक माह का समय दिया जायेगा।

12—आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरांत अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13—उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा-पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14—यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग-पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।

विवाद—उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत को संदर्भित किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश अभ्यर्थकों पर बन्धनकारी होगा।

(त) सामान्य अनुदेश (General Instructions)

1—भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। 200 मीटर से 1.5 किलो मीटर के दायरे में निर्माण की मंजिलों एवं ऊँचाई की अनुमति तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जाएगी।

2—भू-खण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

3—भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) वाहन पार्किंग, बेसमेंट वाहन पार्किंग, भंडारण व सुविधाओं के रख-रखाव व सेवा तल (Service Floor) भंडारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाए तो इनका क्षेत्रफल एफ०ए०आर० में शामिल नहीं होगा।

4—निकटतम हवाई अड्डा चाहे विमानापत्तम प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो के 5 किमी० की परिधि में 30 मी० से ऊँचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

5—उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो, कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-आच्छादन, फ्लोर एरिया रेशियों (FAR) अथवा अधिकतम ऊँचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6—उपरोक्त सूची में उल्लिखित, भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण, जिला पंचायत द्वारा इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7—मल्टी लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेंट अनुमन्य होंगे।

8—इन उपविधियों के अधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।

9—इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सी०आर०पी०सी० की धारा 133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(थ) अनुज्ञा की शर्तें

अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरांत यदि यह संज्ञान में आये की नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी हैं अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal) किया जा सकता है।

(क) अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा की वह अभियंता जिला पंचायत की संस्तुति पर वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दे।

(ख) पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिज़ाईन वास्तुविद के अंतर्गत कार्य करने वाले योग्य अभियंता द्वारा कराया जाएगा।

(ग) कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाईसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(द) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत कन्वोज यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन रु0 1,000.00 तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रुपये 50 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जोकि तीन माह तक हो सकेगा।

डा० राज शेखर,
आयुक्त,
कानपुर मण्डल, कानपुर।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 06 मई, 2023 ई० (बैशाख 16, 1945 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

I, Alok Srivastava, R/o 41A/2 Saket Nagar, Jayantipur, Dhoomanganj, Prayagraj, humbly inform to all that in my some educational documents my father's name mentioned as N. B. SRIVASTAVA where as all other documents it is mentioned in full form as NAND BABU SRIVASTAVA. Therefore please consider both the name related to single person, i.e. my late father's name.

ALOK SRIVASTAVA.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का सही नाम मंगत राम मल्होत्रा है। जो उनके शैक्षिक अभिलेखों, आधार कार्ड व पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट के सह अंक प्रमाण पत्रों में जिनका अनुक्रमांक क्रमशः हाई स्कूल 5026440 है तथा इण्टरमीडिएट 23707031 है। मेरे पिता का नाम मंगत मल्होत्रा अंकित हो गया है जो गलत है।

वरदान मल्होत्रा,
पता : 1068 मीरापुर,
जिला प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स प्रधान कान्ट्रक्टर्स (इण्डिया) पता-प्रधान मार्किट/निवास मैन चौक निकट पुलिस स्टेशन ककोड, तहसील सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश की पार्टनर्स शिप 17 मार्च, 2017 को हुई थी जिसमें क्रमशः दो साझेदार थे। श्री महेश चन्द्र गुप्ता पुत्र स्व० श्याम लाल गुप्ता जी व श्री मोहन सिंह पुत्र श्री भवर सिंह जी थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को साझेदार नं० 2 श्री मोहन सिंह पुत्र श्री भवर सिंह जी स्वेच्छा से इस फर्म से अलग हो गये हैं तथा इनका फर्म से कोई लेना-देना बकाया नहीं है तथा अब इनकी जगह दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को नई साझेदार श्रीमती भावना गुप्ता पत्नी श्री महेश चन्द्र गुप्ता जी स्वेच्छा से इस फर्म में साझेदार हो गई है। तथा अब इस फर्म में क्रमशः दो साझेदार ही रहेंगे। 1-श्री महेश चन्द्र गुप्ता पुत्र स्व० श्याम लाल गुप्ता, 2-श्रीमती भावना गुप्ता पत्नी श्री महेश चन्द्र गुप्ता हो गई है।

महेश चन्द्र गुप्ता,
साझेदार,

मेसर्स प्रधान कान्ट्रक्टर्स इण्डिया पता-प्रधान
मार्किट/निवास मैन चौक निकट पुलिस स्टेशन ककोड,
तहसील सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

मेसर्स क्रिस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर के भागीदार नईम अख्तर पुत्र श्री अख्तर अली ने दिनांक 08 अप्रैल, 2021 को फर्म से त्याग-पत्र दे दिया है तथा श्री अनमोल वर्मा दिनांक 08 अप्रैल, 2021 को इस फर्म में शामिल हो गये हैं।

वर्तमान में मेसर्स क्रिस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर में दो भागीदार हैं जिनके नाम-1-श्री नदीम अख्तर, 2-श्री अनमोल वर्मा हैं।

उपरोक्त सभी बातें सही व सत्य हैं।

नदीम अख्तर।

सूचना

मैं ब्रजेश पाण्डेय मेरे पुत्र अंकित कुमार पाण्डेय के हाईस्कूल सन् 2022, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड में मेरा और मेरे पत्नी का नाम ब्रजेश कुमार पाण्डेय और रिकी पाण्डेय गलत अंकित कर दिया गया है, जबकि मेरा और मेरे पत्नी का सही नाम ब्रजेश पाण्डेय और रिकी देवी है।

ब्रजेश पाण्डेय,

पता-मुल्लनपुर, पी0एस0सी0, वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम निखर साहू है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 980494214647 में घर का नाम छवि साहू अंकित हो गया है उपरोक्त दोनों नाम मेरी पुत्री का ही हैं। भविष्य में मेरी पुत्री को निखर साहू पुत्री लवकुश साहू के नाम से जाना एवं पहचाना जाये।

लवकुश साहू,

पता-तिगनौता डांडी, नैनी, जिला प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स अरमान एग्रो फूड, पता मुड़िया हाफिज, धौरा टॉडा, तहसील व जिला-बरेली-243202 जिसकी पंजीकरण सं0 BAR/0014626 है, यह फर्म दिनांक 22 अगस्त, 2022 से निरन्तर सुचारु रूप से कार्य कर रही है, उपरोक्त फर्म से साझेदार मोहम्मद ताहिर पुत्र श्री मोहम्मद मूसा, निवासी मोहल्ला बाघ, धौरा टॉडा, जिला बरेली, उ0प्र0-243202 दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये हैं, तथा मोहम्मद ताहिर का फर्म पर व फर्म का मोहम्मद ताहिर पर कोई शेष बकाया नहीं है। उपरोक्त फर्म में वर्तमान में कुल छः साझेदार क्रमशः श्री मोहम्मद यासीन, मो0 यामीन, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद आशिफ हैं। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त साझेदारी के संसोधन के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मो0 यासीन,

साझेदार,

मेसर्स अरमान एग्रो फूड,

पता-मुड़िया हाफिज, धौरा टॉडा,

तहसील व जिला-बरेली-243202

जिसकी पंजीकरण सं0-BAR/0014626

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s. SHRI BALAJI HOSPITALITY पता-398, Moti Nagar, Lucknow-226004 जिसका रजि0 नं0 LUC/0005625 दिनांक 21 जनवरी, 2020 को पंजीकृत है, उक्त फर्म में प्रथम पार्टनर, राजेश अग्रवाल द्वितीय पार्टनर, मुकेश गुप्ता, तृतीय पार्टनर, नीरज जौहर, चतुर्थ पार्टनर, शैलेन्द्र रस्तोगी, पंचम पार्टनर, अखिलेश रस्तोगी, षष्ठम पार्टनर, उमेश चन्द्र गुप्ता साझीदार थे तत्पश्चात् सातवें पार्टनर, सुधीर कुमार साहनी को दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से साझीदारी में सम्मिलित किया गया है।

वर्तमान में प्रथम पार्टनर, राजेश अग्रवाल द्वितीय पार्टनर, मुकेश गुप्ता, तृतीय पार्टनर, नीरज जौहर, चतुर्थ पार्टनर, शैलेन्द्र रस्तोगी, पंचम पार्टनर, अखिलेश रस्तोगी, षष्ठम पार्टनर, उमेश चन्द्र गुप्ता तथा सप्तम पार्टनर, सुधीर कुमार साहनी साझीदार होंगे।

राजेश अग्रवाल,
पार्टनर,

M/s. SHRI BALAJI HOSPITALITY,
पता-398, Moti Nagar, Lucknow-226004.

NOTICE

I, Aatish Singh S/o Ram Bhawan Singh R/o 119/99 Bamba Road Darshanpurwa, Kanpur Nagar U. P.-208012 declare that name of my mother has been wrongly written as SHIR KUMARI SINGH in my 12th 'C.B.S.E.' Marksheet/Certificate Roll no. 5689041 Year 2013. The Actual name of my mother is SHIV KUMARI SINGH, which may be amended accordingly.

Aatish Singh,
Deponent.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी भारतीय जीवन बीमा निगम की पालिसी सं0 310421003 में घर का नाम मानस मौर्य अंकित हो गया है जबकि मेरा सही नाम ईशान मौर्य पुत्र शिवमूरत मौर्य दोनों ही नाम शपथकर्ता का है। भविष्य में मुझे ईशान मौर्य पुत्र शिवमूरत मौर्य के नाम से जाना व पहचाना जाये।

ईशान मौर्य पुत्र शिवमूरत मौर्य,
निवासी-61डी/3सी/7जी ओम गायत्री नगर,
चांदपुर सलोरी, प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का सही नाम वकील अहमद (VAKEEL AHMAD) है। जो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश

मेरे हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट के सह अंक प्रमाण-पत्र जिसका अनुक्रमांक क्रमशः 23217479 तथा 23688730 है, जिसमें मेरे पिता का नाम वकील कामरान (WAKEEL KAMRAN) अंकित हो गया है।

अम्माराह कामरान (Ammarah Kamran),
631/137, मुलायम नगर, इस्माइलगंज,
इंदिरा नगर, लखनऊ, उ0प्र0-226016

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र के हाई स्कूल के सह अंक प्रमाण-पत्र में मेरा नाम राम चन्द्र केसरी तथा पत्नी का नाम गीता केसरी, अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरा तथा मेरी पत्नी का सही नाम क्रमशः राम चन्द्र केसरवानी तथा गीता केसरवानी है।

राम चन्द्र केसरवानी,
नि0-1/6, बी0 माधवकुंज कटरा,
तहसील-सदर, जिला प्रयागराज।

सूचना

फर्म मेसर्स ताज ट्रेडमार्क, आनन्द वृन्दावन, संजय प्लेस आगरा-282002 पत्रावली संख्या-एजीआर-0002284 में दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को सौभाग्य कृष्ण अरोरा पुत्र श्री नवीन कृष्ण अरोरा, निवासी-बी-62/4 केशव कुंज, प्रताप नगर, आगरा फर्म की साझेदारी में सम्मिलित हुये वर्तमान फर्म में भागीदार श्री प्रभात कृष्ण अरोरा, श्री नवीन कृष्ण अरोरा, श्री महान कृष्ण अरोरा, श्री आनन्द कृष्ण अरोरा, श्रीमती रुचि अरोरा एवं श्री सौभाग्य कृष्ण अरोरा है।

प्रभात कृष्ण अरोरा,
साझेदार,
मेसर्स ताज ट्रेडमार्क,
आनन्द वृन्दावन,
संजय प्लेस आगरा-282002

सूचना

फर्म मेसर्स गांधी ज्वैलर्स, पता-रेलवे रोड़, अलीगढ़ पत्रावली संख्या-एजी-13221 में दिनांक 06 जुलाई, 2019 को श्रीमती सरला देवी की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उनके उत्तराधिकारी गौरव गांधी पुत्र स्व0 हरीश चन्द्र गांधी निवासी-शाह पाड़ा, अलीगढ़ फर्म की साझेदारी विलेख दिनांक 08 जुलाई, 2019 में सम्मिलित हुये, तथा फर्म की द्वितीय साझेदार श्रीमती शिवानी गांधी द्वारा अपने नाबालिग पुत्र मास्टर मासूम गांधी को अपनी हिस्सेदारी दे दी है मासूम गांधी के व्यस्क होने तक श्रीमती शिवानी

गांधी उनकी संरक्षक रहेगी वर्तमान फर्म में साझेदार गौरव गांधी एवं मास्टर मासूम गांधी है।

गौरव गांधी,
साझेदार,
मेसर्स गांधी ज्वैलर्स,
पता-रेलवे रोड़, अलीगढ़।

सूचना

सूचित किया जाता है भागीदारी फर्म मेसर्स नारायण एसोसियेट्स नारायण पुरी विलेज, डहरूआ, जिला मथुरा, उ0प्र0 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं -

फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से श्रीमती कुसुम भारद्वाज पत्नी मुरारी लाल भारद्वाज, निवासी 16, कृष्णा पुरी, मथुरा व श्री मनमोहन पुत्र श्री राम स्वरूप उपाध्याय, निवासी 547, रोशन विहार कॉलोनी, यमुना पार, लोहवन, मथुरा, उ0 प्र0 'नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हुये तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को फर्म के पूर्व प्रथम पक्ष भागीदार श्री मुकेश चन्द पुत्र स्व0 अतर सिंह, द्वितीय पक्ष श्री तारा चन्द पुत्र स्व0 अतर सिंह व तृतीय पक्ष श्रीमती किरन देवी पत्नी स्व0 अतर सिंह, निवासीगण गांव डहरूआ पोस्ट लोहवन, तहसील मांट, जिला मथुरा अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं और उक्त दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से श्री हरीश चन्द्र चतुर्वेदी पुत्र श्री राम प्रसाद चतुर्वेदी, निवासी 125, ब्लाक डी, कृष्णा नगर, मथुरा, उ0 प्र0 व श्री सुरेश चन्द्र शुक्ला पुत्र श्री रंगी लाल शुक्ला, निवासी 55, अम्बेडकर कॉलोनी, रघुवीर विहार, मथुरा उ0प्र0 नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं। अब वर्तमान में श्रीमती कुसुम भारद्वाज, श्री मनमोहन, श्री हरीश चन्द्र चतुर्वेदी तथा श्री सुरेश चन्द्र शुक्ला भागीदार हो गये हैं।

कुसुम भारद्वाज,
भागीदार,

मेसर्स नारायण एसोसियेट्स नारायण पुरी विलेज,
डहरूआ, जिला मथुरा, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का सही नाम अजय कुमार त्रिपाठी है, जो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं अन्य अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल के सह अंक व प्रमाण-पत्र (अनुक्रमांक-23283246) में 'अजय त्रिपाठी' अंकित हो गया है जो की गलत है।

अंजली त्रिपाठी,
पुत्री अजय कुमार त्रिपाठी,
पता-बी-2/262-1, भदौनी,
वाराणसी-221001